

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 309/2016

महेन्द्र सिंह

—अपीलार्थी

## बनाम

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, झुंझुनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.02.2016

आदेश की दिनांक : 03.05.2024

## उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 24.10.1986 को अस्थाई तौर पर अध्यापक ग्रेड-तृतीय के पद पर हुई थी। अपीलार्थी स्क्रीनिंग वर्ष 1989 में हुई। उसके पश्चात अपीलार्थी को उसी पद पर कार्यरत रखा गया। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 24.10.1995 को उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से गणना करते हुए दिया गया, परंतु द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के समय अपीलार्थी की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक 24.10.1986 से नहीं की गई, बल्कि स्क्रीनिंग की दिनांक 01.05.1989 से की गई। अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है, परंतु उसे वह लाभ नहीं दिया गया है। अपीलार्थी ने न्याय की मांग हेतु एक नोटिस भी प्रत्यर्थी विभाग को दिया, परंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 24.10.1986 से गणना करते हुए दिया जाए।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी को नियमानुसार एसीपी का लाभ दिया गया। विधि अनुसार नियमित नियुक्ति/स्क्रीनिंग पश्चात् पारित आदेशों के अनुसार ही दिनांक 16.02.1990 से सेवा संबधित समस्त लाभ परिलाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी होने से उक्त अपील मय कोस्ट के काबिल निरस्त योग्य हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम् जगदीश नारायण चतुर्वेदी मे पारित विनिश्चय

के अनुसार अपीलार्थी स्थायीकरण तिथि/नियमित नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबंधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है, अपीलार्थी विधि अनुसार देय परिलाभ स्वीकार एवं अंगीकार करते हुए आ रहा है और बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए लम्बे विलम्ब बाद बिना और विलम्ब क्षम्य की प्रार्थना के बिना ही सारहीन एवं निरर्थक तथ्यों के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की उक्तानुसार अपील अपीलार्थी मय कोस्ट निरस्त योग्य है जो निरस्त फरमाई जावे।

3. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.10.1986 के द्वारा हुई थी, जो आदेश अनुलग्नक-1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उक्त नियुक्ति आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अस्थाई तौर पर की गई थी। नियुक्ति आदेश से यह स्पष्ट है कि मेरिट के आशार्थी उपलब्ध होने तक अथवा अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अस्थाई आधार पर अध्यापकों के पद पर नियुक्ति दी गयी। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति नहीं थी, बल्कि अपीलार्थी को तदर्थ (ad-hoc) आधार पर नियुक्ति दी गई थी। अपीलार्थी के सेवाएं स्क्रिनिंग के पश्चात नियमित की गई है।
4. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent -

employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

5. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में यह माना गया है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। यह भी माना है कि वरिष्ठता या अन्य लाभ के संबंध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारीख नहीं हो सकती। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी को अस्थाई तौर पर तदर्थ आधार पर जो सेवाएं प्रदान की थी, उसे अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लाभ के लिए नहीं जुड़वा सकता है। अपीलार्थी को नियमितिकरण की दिनांक से ही नियमित होना मानते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है।
6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)  
सदस्य (न्यायिक)